

# समाजवादी जन परिषद

## एक परिचय

राष्ट्रीय कार्यालय

१८, जलधारा, राजेन्द्र नगर

पुणे (महाराष्ट्र)

राज्य कार्यालय

क्वार्टर नं०-६ रोड नं० ३०

गर्दनी बाग, पटना

## समाजवादी जन परिषद क्या है ?

मौजूदा राजनैतिक परिदृश्य में तमाम स्थापित राजनैतिक दल अप्रासंगिक हो गये हैं। विकल्प के नाम पर चित्री पिटी राजनैतिक पाठियां ही नये नामों के आवरण में आ रही हैं, जिनके राजनैतिक विन्तव्य प्रणाली में श्रद्भूत साम्य है। दूसरी तरफ देश के अन्दर स्थापित राजनैतिक दलों से इतर शोषित-पीड़ित तबकों के जनान्दोलन भी चल रहे हैं। देश के ऐसे जनान्दोलनों के समन्वय से एक नया राजनैतिक दल **समाजवादी जन परिषद** के नाम से (३१ दिसम्बर ६४— १ जनवरी ६५ को महाराष्ट्र के ठाणे में) अस्तित्व में आया है। इस दल के नीति वक्तव्य के महत्वपूर्ण अंश को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

आज का सम्पूर्ण राजनैतिक तंत्र जनता की भ्यूनतम आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। कांग्रेस से तो लगभग देश भर की जनता का मोह भंग हो चुका है। गैर-कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस से गुणात्मक रूप में भिन्न साबित नहीं हुई हैं। क्योंकि उनके पास कोई वैचारिक विवत्प नहीं है। नतीजतन कोई भी दल सत्ता में रहा, वास्तविक शक्ति एक छोटे से सामाजिक वर्ग या समूह के हाथ में ही रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर में अधिक गतिशील समूह सत्ता के केन्द्र में आयेगे। जिनके हितों का राष्ट्रीय हितों से सीधा टकराव है। शासक वर्ग का यह नया चेहरा भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक पहलू है। समाजवादी जन परिषद स्थापित राजनीति के ढर्रे से अलग हट कर लोकतांत्रिक धारा को मजबूत करने के लिए कृत-संकल्प है, तथा स्थापित राजनीति का प्रभावी विकल्प बनना चाहती है। साथ ही वर्तमान राजनैतिक ढाँचे का अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण करने को कृत-संकल्प है। लेकिन इसका दीर्घ-कालिक लक्ष्य केन्द्रीकरण और समरूपीकरण पर आधारित आधुनिक राजनैतिक ढाँचे को बड़ाकर एक विकेन्द्रित और विविधता सम्पन्न लोकतांत्रिक ढाँचे का निर्माण करना है।

**वैश्विक विपत्तियों की नीतियों** :—तीसरी दुनिया के आजाद देशों की नीतियों के कारण विषमतापूर्ण विश्व-व्यवस्था बनी रही। अमीर देशों के अन्धानुकरण के कारण वे तकनीक, विशेषज्ञ, उपभोक्ता सामग्री और पूँजी के लिए अमीर देशों पर निर्भर रहे। इसके लिए कच्चे मालों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात कम कीमत पर करना पड़ा। इससे आयात का खर्चा पूरा न होने पर कर्ज लिया गया। इस प्रक्रिया में कर्ज का बोझ बढ़ता गया।

साम्राज्यवाद के गर्भ से पैदा हुई यह विश्व-व्यवस्था आज भी विषम है। अमीर देशों में रह रहे २०% लोग लगभग ८०% संसाधनों की खपत

कर रहे हैं। २०० वर्ष पूर्व अमीर तथा गरीब देशों की आमदनी का फर्क १.५/१ था जो १९८० में ४३/१ हो गया। विश्व बैंक के अनुसार १९७८ में कम विकसित देशों का विश्व आमदनी में हिस्सा ५.६% था, जो १९८४ में घट कर ४.५६% हो गया। तीसरी दुनिया पर १९८० में कर्ज ८० हजार करोड़ डालर थी जो अब १५० हजार करोड़ डालर हो गई है। जल, जमीन और हवा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अम्लीय वर्षा बढ़ रही है, तथा कार्बन डायऑक्साइड एवं अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण "ग्रीन हाउस" प्रभाव बढ़ रहा है। पर्यावरण की यह स्थिति तब है जबकि आधुनिक विकास दुनिया के ३०% लोगों को उपलब्ध है। यदि बाकी ७०% लोग भी उन्हीं की तरह का उपभोग स्तर प्राप्त करें तब विकास का प्राकृतिक आधार ५-१० वर्षों में ही समाप्त हो जायेगा। वर्तमान में पेट्रोलियम का ज्ञात भण्डार ४२ वर्ष चलेगा, प्राकृतिक गैस ५६ वर्ष और कोयला ७७ वर्ष।

वैकल्पिक विकास नीति के निर्माण के लिए वैकल्पिक मूल्य तथा जीवन-दृष्टि विकसित करना होगा। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग तथा विषमता के स्थान पर समता का आदर्श विकास की वैकल्पिक अवधारणा के लिए आवश्यक है तथा तकनीक के प्रश्न पर स्पष्ट दृष्टि होना जरूरी है। वैकल्पिक तकनीक का चयन करते वक्त हमारी प्रमुख कसौटियां मानव श्रम को आसान करना, बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति, प्राकृतिक सांसाधनों की सुरक्षा, सबको रोजगार, सामाजिक समता, विकेन्द्रीकरण तथा विदेशी निर्भरता से मुक्ति होगी।

**आर्थिक नीतियाँ :-** समाजवादी जन परिपद की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करना तथा एक समतामूलक विकास-नीति के तहत अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा, इसका मतलब आजाद भारत की अर्थ-व्यवस्था ( जिसे "नेहरूवादी" कहा जाता है) को जीवित करना नहीं है। दरअसल १९९०-९२ में उठाये गये आर्थिक सुधार के कदम नेहरूवादी नीति की ही तार्किक परिणति है। हम नौकरशाही द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उद्यमों की अर्थ-व्यवस्था और अबाध निजीकरण दोनों के विरोधी हैं। हमारी आर्थिक नीतियों के ठोस लक्ष्य होंगे—आय-व्यय की असमानता को निश्चित सीमा में बाँधकर समता की ओर बढ़ना, क्षेत्रों और समूहों के बीच विषमता को पाटना, लोगों की बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, पर्यावरण की रक्षा तथा विदेशी नियंत्रण और निर्भरता की समाप्ति। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अर्थ-व्यवस्था के हर क्षेत्र में अनेक नीतियों, कार्यक्रमों को अपनाना होगा। आज का अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध प्राकृतिक साधनों के दोहन पर टिकी है। इससे कई समस्याएँ पैदा हुई हैं। गैट तथा डंकल प्रस्ताव के जरिये

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमन में नये विषयों को लाया गया है। इसके अनेक दुष्परिणाम हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विष्व बैंक तथा गैंट के तिहरे समन्वित हमले को रोकने के लिए भारत को इन सस्थाओं से बाहर आने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि ये संस्थायें दादागिरी और लूट का माध्यम हैं। इसके लिए जन-मानस को तैयार करना जरूरी है। समाजवादी जन परिषद इन विचारों के प्रचार-प्रसार को अपनी पहली जिम्मेवारी मानती है।

**कृषि और किसान :**— भारतीय समाज के सन्तुलित विकास के लिए कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद एकाध अभाव को छोड़ कर कृषि क्षेत्र को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

औद्योगिक वस्तुओं और कृषि-जन्य वस्तुओं के मूल्यों के असम्बुलन एवं रसायनिक खाद आदि पर सबसिडी खत्म करने से किसानों का घोर शोषण होता है। केवल कृषि आय पर निर्भर किसानों की संख्या नगण्य है। कुछ अन्नदातों को छोड़ कर भारतीय किसान एक कमजोर और शोषित समूह है। समाजवादी जन परिषद की आस्था गाँवों में है। हमारी विकेंद्रित औद्योगिक विकास की बलवना में गाँव का आधा रोजगार छोटे उद्योगों से होगा, तथा पर्याप्त संख्या में लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम मिलेंगे। इससे कृषि पर बढ़ रहे दबाव समाप्त हो जायेंगे। भारतीय कृषि नीति का पहला लक्ष्य होगा स्वास्थ्य के लिए तथा एक न्यूनतम जीवन-स्तर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसके उत्पादन की क्षमता किसानों के पास है, इस अवधारणा को पुष्ट करना। हम निर्यात विकास के सिद्धांत के खिलाफ हैं, खास कर कृषि क्षेत्र में निर्यात के। बीजों के संरक्षण, संवर्द्धन, भण्डारण, कृषि उपकरणों का निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था गाँवों में तथा गाँव के आसपास उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। किसानों के उत्पादन क्षमता तथा उत्पाद को जिला प्रशासन दबा कर रखती है। इसलिए किसानों की आजादी के लिए हम जिला प्रशासन के वर्तमान ढाँचे को खत्म करने के पक्ष में हैं। हम हृदयवन्दी कानून को लागू करने की माँग के साथ जिन्हें उद्योग या प्रशासन में रोजगार प्राप्त है, उनकी भूमि से मितिकयत समाप्त करने की माँग करते हैं। हम साम्राज्यवादी बाजार के विरुद्ध हैं। कृषि विकास और भूमि सुधार की नीतियों को अपनाने के उद्देश्यों को लेकर एक नये किसान आंदोलन को संगठित करने का दायित्व समाजवादी जन परिषद स्वीकार करती है।

**उद्योग नीति :**— इससे जुड़ी औद्योगिक-नीति होगी जो परिसराभिमुख होगी—यानी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के अलग-अलग परिसर होंगे, और इस तरह कुछ वस्तु का उत्पादन गाँव की आवश्यकता को ध्यान में रख कर होगा, कुछ का प्रखण्ड और कुछ का जिला

या पूरे राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार। इसे भी केन्द्रीकरण और क्षेत्रीय विषमता पर रोक लगेगी और आत्म-निर्भरता बढ़ेगी। इन उद्यमों में अधिक से अधिक नवीकरण किए जाने योग्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होगा जैसे—पेट्रोलियम और कोयले की जगह वायु, जल-स्रोतों, सौर ऊर्जा एवं गोबर गैस आदि।

**क्षेत्रीय विषमता**—यूरोपीय देश की औद्योगिक विकास अपनाने के परिणामस्वरूप तीसरी दुनिया में एक ही राष्ट्र में कुछ क्षेत्र विशाल भूभाग का शोषण करने लगे। कृषि-शोषण और गाँवों की लूट इसी प्रक्रिया के नमूने हैं। इसका सबसे उग्र-स्वरूप है कुछ भौगोलिक क्षेत्रों की लूट और शोषण, जैसे पूरे बिहार और विशेष कर छोटा नागपुर।

क्षेत्रीय विषमता की इस प्रक्रिया का राजनैतिक प्रतिकार करना समाजवादी जन परिषद के प्रमुख उद्देश्यों में से एक होगा। इसका विकल्प विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता है। लेकिन अलग राज्य या राष्ट्र नहीं। हम छोटे राज्यों मसलन झारखण्ड और उत्तराखण्ड के सिद्धांत रूप में समर्थक हैं। पर हम अलगाववाद के विरोधी हैं। समाजवादी जन परिषद् इन सब शोषित क्षेत्रों के लिए असरदार राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की समर्थक है।

**जाति व्यवस्था उन्मूलन**—भारतीय संदर्भ में समता के आदर्श को स्वीकार करने का मतलब है जाति व्यवस्था का विरोध। क्योंकि समाज में गैर-बराबरी, अन्याय और शोषण का सबसे प्रमुख स्वरूप जाति व्यवस्था रही है। समाजवादी जन परिषद यह मानता है कि जाति व्यवस्था का नाश किसी सरल और एकांगी तरीके से नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा जैसे—

- i वैचारिक—जाति-निमूलक चेतना का निर्माण।
- ii सामाजिक—जाति विरोध और अन्तर्जातीय व्यवहार।
- iii आर्थिक—पिछड़ी दलित जातियों के सामर्थ्य में वृद्धि।
- iv राजनैतिक—लोकतंत्र का विस्तार।
- v शासकीय—आरक्षण की व्यवस्था आदि।

आरक्षण की नीति हमारे लिए एक हथियार है जाति व्यवस्था को तोड़ने का, जातीय बैमनस्य फैला जाति आधारित गुटों की राजनीति करने का नहीं, जैसा जनता दल और समता पार्टी कर रही है।

**नर-नारी समता**—आज के पुरुष प्रधान समाज में औरत-मर्द के संबंध का स्वरूप संस्थागत विषमता का है। इससे औरतों के शोषण के साथ मर्दों का व्यक्तित्व भी संकुचित और विकृत होता है। नर-नारी समता का कोई बना-बनाया और विश्वसनीय मॉडल आज हमारे सामने नहीं है। समतामूलक आंदोलन में नर-नारी समता के प्रश्न पर चेतना विकसित करना जरूरी है। इस सम्बन्ध में स्वतंत्र नारी संगठनों की राजनीति को प्रभावी बनाने के लिए इसे व्यापक समतामूलक आंदोलन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। इसके लिए कार्यक्रम और मांग समाजवादी जन परिषद ने निश्चित किये हैं।

हमारा प्रयास अपने संगठन में औरतों का अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का होगा ।

**साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता**—साम्प्रदायिकता के विकल्प में हम धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं । पिछले वर्षों में भाजपा, विहिप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हिन्दू भावना का उभार खतरनाक प्रवृत्ति है । साथ ही साम्प्रदायिकता के अन्य स्वरूप भी खतरनाक है । अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता को और आक्रामक बनाती है । साम्प्रदायिकता के विरोध में सामाजिक-आर्थिक पहलू को भी समाजवादी जन परिषद उजागर करेगी ।

**शिक्षा नीति**—आज के भारत में शिक्षा के प्रश्न पर एक समग्र सोच बनाने की जरूरत है । शिक्षा में आमूल सुधार के लिए जरूरी है कि हम एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करें और उसका व्यवहारिक स्वरूप निरूपित करें । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास यानी बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक सभी पक्षों के विकास का साधन बन सके और एक समतामूलक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में योगदान करे । तत्काल हम सबों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे ।

**लोकतंत्र और चुनाव**—स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहली और बुनियादी गत है । एक जीवन्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आम जनता के शक्तिकरण का सबसे प्रमुख जरिया हो सकता है और इस नाते चुनावी राजनीति परिवर्तन की शक्तियों का एक अहम हथियार बन सकती है । गैर चुनावी राजनीति का अनुभव यह दिखलाता है कि चुनाव में भागीदारी के ही नहीं, चुनाव से परहेज के भी अपने खतरे हैं । स्थानीय जनता के प्रति सीधी जवाबदेही सुनिश्चित करनेवाली किसी प्रक्रिया के अभाव में ऐसी राजनीति अक्सर समाज के मुख्य धारा से कट जाती है । और उसके फँलाव की सम्भावना नहीं रहती । इसी अनुभव के कारण वैसे अनेक आंदोलनकारी संगठन जो इसके पूर्व चुनावी राजनीति से अलग थे, राजनीति की अनिवार्यता को कबूल कर समाजवादी जन परिषद का गठन कर चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने की नीति अपना रहे हैं । लेकिन चुनावी राजनीति के भटकाव से बचने के लिए समाजवादी जन परिषद चुनावी राजनीति को सतत संघर्ष और रचना से जोड़ कर चलने को कृत संकल्प है । साथ ही चुनाव में हिस्सा लेने के लिए संगठन और प्रत्याशियों दोनों पर कुछ मर्यादाएँ निभाने का बंधन डालती है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है—सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ना जहाँ संगठन का व्यापक जनाधार हो जिसके अभाव में प्रत्याशी जाति पंसा या अन्य हथकंडों का सहारा लेते हैं ।

आज देश और विशेष कर बिहार में जो एक राजनीतिक शून्यता है उसके एक सच्चे विकल्प के लिए समाजवादी जन परिषद राज्य के तमाम शोषित-पीड़ित जनता और प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती है कि जनशक्ति को नई दिशा के इस प्रयास में पूरी भागीदारी करें ।